आई.एल.आर.पंजाब एंड हरियाणा

समक्ष अनिल क्षेत्रपाल, जज
सुभाष खोबरा – याचिकाकर्ता
बनाम
हरियाणा राज्य सरकार और अन्य – उतरवादीगण
सी.डब्लू.पी. नम्बर, 21006 ऑफ़ 2020
16 दिसम्बर, 2020

भारत का संविधान, 1950 - अनुछेद 141 और 226 - रिट याचिका जिसमें आवश्यकताओं/मानदंडों में ढील देने के निर्देश दिए जाने की मांग की गई है - रिट परमादेश कब जारी किया जा सकता है - घूरने के निर्णय, प्रति इंक्यूरियम और सब साइलेंटियो के सिद्धांत - बाध्यकारी होने पर समन्वय और डिवीजन बेंच के निर्णय - याचिकाकर्ता ने अदालत से संपर्क कर यह मांग की निर्धारित मानदंडों/दिशानिर्देशों में ढील देकर पेट्रोल पंप डीलरशिप के लिए 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' जारी करने का निर्देश, और अंत में न्यायालय के समन्वय और डिवीजन बेंच के निर्णयों के आधार पर उनके प्रतिनिधित्व पर निर्णय लें - परमादेश की एक रिट आयोजित की गई अधिकारियों को छूट देने का निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है - छूट से इनकार करने पर एक रिट याचिका दायर की जा सकती है - परमादेश की रिट तब जारी की जा सकती है जब याचिकाकर्ता अपने कानूनी और न्यायिक रूप से लागू करने योग्य अधिकार और उत्तरदाताओं के पालन करने के कानूनी कर्तव्य को स्थापित करता है - पाया गया था की याचिकाकर्ता को ऐसा कोई अधिकार नहीं था, और केवल उत्तरदाताओं को निर्णय लेने के लिए आदेश देने का अधिकार था। आगे कहा गया, समन्वय और डिवीजन बेंच के उद्धृत निर्णय अनुच्छेद 141 के तहत बाध्यकारी उदाहरण नहीं थे क्योंकि न तो कानून का प्रश्न उठाया गया था। न ही उसमें निर्णय लिया गया कि सिंथेटिक एंड केमिकल्स लिमिटेड मामले (1991) 4 एससीसी 139 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया, जिसने एक ऐसा निर्णय लिया जो स्पष्ट नहीं था और कारणों पर आधारित नहीं था और न ही यह मुद्दों पर विचार करके आगे बढ़ा और इसे एक निर्णय नहीं माना जा सकता है। कानून को बाध्यकारी प्रभाव वाला घोषित किया गया - समिति को अंतिम निर्णय का निर्देश देकर याचिका का निपटारा किया गया।

माना गया कि, इससे पहले कि यह अदालत याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों पर विचार करे, विचार के लिए जो मौलिक प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या अदालत के लिए अधिकारियों को मानदंडों में ढील देने के लिए परमादेश रिट जारी करना उचित है। इंडियन रोड्स कांग्रेस एक विशेषज्ञ संस्था है। इसने अधिकारियों द्वारा पालन किए जाने के लिए कुछ दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। कोर्ट को इंडियन रोड्स कांग्रेस के सदस्यों से अधिक तकनीकी ज्ञान नहीं है। इसके अलावा, परमादेश रिट तब जारी की जा सकती है जब याचिकाकर्ता यह स्थापित कर ले कि उसे कानूनी कर्तव्य निभाना है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता के पास, इस न्यायालय के विचाराधीन, ऐसा कोई अधिकार नहीं है जो न्यायिक रूप से प्रवर्तनीय हो। इसमें कोई संदेह नहीं है, याचिकाकर्ता को केवल प्रतिवादियों को इस पर निर्णय लेने का आदेश देने का अधिकार है।

(पैरा 9)

आगे कहा गया कि, इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि किसी भी मामले में, न्यायालय ने इस मुद्दे की जांच नहीं की है कि क्या प्रतिवादियों को छूट देने का निर्देश देने के लिए परमादेश की रिट जारी की जा सकती है। छूट से इनकार करने पर रिट याचिका दायर की जा सकती है। हालाँकि, इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में, अधिकारियों को छूट देने का निर्देश देने वाला परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। यह तय है कि ऐसे निर्देश संभवतः जारी नहीं किए जा सकते हैं ताकि किसी प्राधिकारी को ऐसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए मजबूर किया जा सके जिसमें विवेक का पर्याप्त तत्व हो।

(पैरा 15)

इसके अलावा यह माना गया कि, इस न्यायालय को जिस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बुलाया गया है वह यह है कि क्या डिवीजन बेंच और समन्वय बेंच द्वारा पारित निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत बाध्यकारी उदाहरण हैं। ऊपर उल्लिखित निर्णयों को ध्यान से पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि न तो प्रश्न उठाया गया और न ही निर्णय लिया गया। इस पहलू पर, दो सिद्धांत हैं। एक है पेर इंक्यूरियम, जबकि दूसरा है सब साइलेंटियो। इन्हें **यूपी राज्य और अन्य बनाम सिंथेटिक एंड केमिकल्स लिमिटेड और अन्य (1991) 4 एससीसी 139** सुप्रीम कोर्ट द्वारा खूबसूरती से समझाया गया है ।

(पैरा 16)

इसके अलावा यह माना गया कि, दिशानिर्देशों में ढील देने की शक्ति केवल एक सक्षम शक्ति है जो किसी को भी अधिकार के रूप में इसकी मांग करने के लिए अधिकृत नहीं करती है। यह प्राधिकार पर अनिवार्य रूप से ढील देने का कर्तव्य भी नहीं डालता है। यह, अधिक से अधिक, सक्षम प्राधिकारी को विवेकाधिकार प्रदान करता है। इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में, दिशानिर्देश जनता की भलाई और सुरक्षा के लिए हैं। यदि ईंधन स्टेशन या रेलवे पर कोई दुर्घटना होती है तो बड़ी त्रासदी से बचने के लिए इन्हें प्रदान किया गया है। इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय को परमादेश रिट जारी करना उचित नहीं लगता।

(पैरा 17)

कार्तिक गुप्ता, अधिवक्ता याचिकाकर्ता के लिए।

आशीष यादव, ए.एडी.जी., हरियाणा। उत्तरदाताओं संख्या 1 से 5 के लिए |

एल.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

अनिल क्षेत्रपाल, जज

(1) याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत निम्नलिखित मूल राहतों की मांग करते हुए यह रिट याचिका दायर की है :-

> "ए) परमादेश की प्रकृति में एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिसमें प्रार्थना की जाए कि ग्राम बालियांवाला में स्थित किसान सेवा केंद्र रिटेल आउटलेट पेट्रोल पंप डीलरशिप साइट के लिए याचिकाकर्ता के पक्ष में "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी करने के लिए प्रतिवादी नंबर 1 से 5 को निर्देश जारी किए जाएं। एमडीआर-1 1. ब्लॉक-टोहाना, जिला फतेहाबाद। भारतीय सड़क कांग्रेस-दिशानिर्देश, 2009 (अनुलग्नक पी 9) में छूट देने के बाद इसे केवल निर्देशात्मक माना गया है और प्रकृति में अनिवार्य नहीं है। - माननीय न्यायालय विभिन्न मामले (अनुलग्नक पी-17);
>
> बी) आगे प्रार्थना करते हुए कि याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद समयबद्ध तरीके से याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन (अनुलग्नक पी -14) पर कार्रवाई करने और अंतिम निर्णय लेने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को निर्देश जारी किए जाएं। काफी समय बीत चुका है और याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट साइट आज तक उत्तरदाताओं द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है;
>
> सी) आगे प्रार्थना करते हुए कि रिटेल आउटलेट के संबंध में याचिकाकर्ता की डीलरशिप रद्द या वापस नहीं ली जाएगी और इस माननीय न्यायालय के समक्ष रिट याचिका विचाराधीन रिटेल

आउटलेट डीलरशिप साइट के लिए आगे आवंटन की प्रक्रिया वर्तमान के लंबित रहने के दौरान शुरू नहीं की जाएगी। "।

(2) इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में, निर्णय के लिए जो प्रश्न उठता है वह यह है कि "क्या राज्य सरकार को उन आवश्यकताओं/मानदंडों में ढील देने के लिए परमादेश जारी करना उचित होगा जो निर्देशिका को स्थापित करने की सुविधा के लिए एक विशेषज्ञ निकाय द्वारा परिचालित की गई थी।" ईंधन स्टेशनों के ऊपर"?

(3) कुछ तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है। एक सार्वजनिक नोटिस के अनुसार, याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने कॉर्पस फंड साइट श्रेणी के तहत गांव बलियानवाला में एमएस/एचएसडी के लिए एक ईंधन स्टेशन (किसान सेवा केंद्र डीलरशिप) के आवंटन के लिए आवेदन किया है। यह दलील दी गई है कि ऐसी श्रेणी के तहत एएनजी आवेदक को भूमि और सुपर स्ट्रक्चर प्रदान करना आवश्यक है, जबकि पंप, टैंक और ऑटोमेशन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। याचिकाकर्ता का दावा है कि वह 2 कनाल 8.5 मरला भूमि का मालिक है और इसलिए, अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत आवेदन करता है। 19.06.2019 को आयोजित ड्रा में उन्हें सफल घोषित किया गया। बताया जाता है कि उन्होंने प्रारंभिक जांच शुल्क जमा कर दिया है। तेल कंपनी की भूमि मूल्यांकन समिति ने साइट का दौरा किया और इसे उपयुक्त पाया। इसके बाद, याचिकाकर्ता की साख के सत्यापन के लिए नियुक्त एक अन्य समिति को भी याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल नहीं मिला। इस प्रकार, 22.09.2019 को एक आशय पत्र जारी किया गया था। आशय पत्र के खंड 10 के अनुसार, याचिकाकर्ता को उचित प्राधिकारी से अपेक्षित "अनापत्ति प्रमाणपत्र" प्राप्त करने के लिए तेल कंपनी की सहायता करने की आवश्यकता थी। खंड 17 में, यह निर्दिष्ट किया गया था कि यह पत्र केवल एक आशय पत्र है और इसे एक ठोस प्रस्ताव के रूप में नहीं माना जा सकता है।

(4) लोक निर्माण विभाग (बी एंड आर) सहित विभिन्न विभागों/प्राधिकरणों में "अनापत्ति प्रमाण पत्र" के लिए विभिन्न आवेदन प्रस्तुत किए गए थे। कार्यकारी अभियंता ने पाया कि याचिकाकर्ता भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा 2009 में प्रकाशित सड़क किनारे ईंधन स्टेशनों की पहुंच, स्थान और लेआउट के लिए दिशानिर्देशों के खंड 4.7 की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, जो वर्ष 2012 में पुनर्मुद्रित किया गया है, जो प्रदान करता है कि ईंधन स्टेशन नहीं होना चाहिए। किसी भी बैरियर और रेलवे लेवल क्रॉसिंग से 1000 मीटर की दूरी के भीतर स्थित है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है :

> “4.7 ईंधन स्टेशन टोल प्लाजा और रेलवे लेवल क्रॉसिंग सहित किसी भी बैरियर से 1000 मीटर की दूरी के भीतर स्थित नहीं होना चाहिए। ईंधन स्टेशन के 1000 मीटर के भीतर कोई चेक बैरियर/टोल प्लाजा नहीं बनाया जाना चाहिए। हालाँकि, यदि ऐसे बैरियर स्थित हैं केवल सर्विस रोड पर और मुख्य कैरिजवे से अलग हैं, तो यह आवश्यकता लागू नहीं होगी। ईंधन स्टेशन रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) के एप्रोच रोड की शुरुआत से कम से कम 200 मीटर और 500 मीटर की दूरी पर और एक ग्रेड की शुरुआत क्रमशः विभाजक या एक रैंप" स्थित होने चाहिए ।

(5) यह दलील दी गई है कि चूंकि सरकार के पास ढील देने की शक्ति है, इसलिए याचिकाकर्ता का मामला समिति को भेज दिया गया। दिनांक 25.06.2020 को एक बैठक आयोजित कर मामला विशेष सचिव की अध्यक्षता में सक्षम समिति को प्रस्तुत किया गया। कार्यपालक अभियंता ने बैठक बुलाने का अनुरोध किया.

दलील दी गई है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि समिति ने साइट के दौरे पर पाया कि जिस साइट की पेशकश की जा रही है वह रेलवे क्रॉसिंग से 695 मीटर की दूरी पर है।

(6) इन तथ्यों में याचिकाकर्ता परमादेश की रिट प्रकृति जारी करने की प्रार्थना करता है।

(7) इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता और उत्तरदाताओं के विद्वान वकील को सुना है जो रिट याचिका की अग्रिम प्रति की आपूर्ति के अनुसार उपस्थित हुए हैं।

(8) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा जारी दिशानिर्देश निर्देशिका हैं और इसलिए, याचिकाकर्ता रिघा के मामले में छूट का हकदार है। उनका कहना है कि विभिन्न मामलों में ऐसी छूट पहले ही दी जा चुकी है। वह, समर्थन में, **"पलविंदर सिंह ओबेरॉय बनाम भारत संघ और अन्य" (सिविल रिट याचिका एनई 14806, 2011, 16.02.2016** को निर्णय लिया गया) (अनुलग्नक पी 17), **"सीमा मक्कड़ बनाम भारत संघ और अन्य"** में दिए गए निर्णयों पर भरोसा करते हैं। " **(सिविल रिट याचिका संख्या 27251 ऑफ़ 2015, फैसला 03.02.2017 को) और दुर्गा दास बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स (सिविल रिट याचिका संख्या 11689, 2012, फैसला 03.12.2013** को)।

(9) इससे पहले कि यह न्यायालय याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की दलीलों पर विचार करे, विचार के लिए मूल प्रश्न यह उठता है कि क्या न्यायालय के लिए अधिकारियों को मानदंडों में ढील देने का निर्देश देते हुए परमादेश जारी करना उचित है। इंडियन रोड्स कांग्रेस एक विशेषज्ञ संस्था है। इसने अधिकारियों द्वारा पालन किए जाने वाले कुछ दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। कोर्ट के पास इंडियन रोड कांग्रेस के सदस्यों से अधिक तकनीकी ज्ञान नहीं है। इसके अलावा, परमादेश की रिट तब जारी की जा सकती है जब याचिकाकर्ता यह स्थापित करता है कि उसके पास कानूनी और न्यायिक रूप से लागू करने योग्य अधिकार है और उत्तरदाताओं को इसका पालन करना कानूनी कर्तव्य के तहत है। पूर्व मामले में, याचिकाकर्ता के पास, इस न्यायालय के विचार में, ऐसा कोई अधिकार नहीं है जो न्यायिक रूप से लागू करने योग्य हो। इसमें कोई संदेह नहीं है, याचिकाकर्ता के पास उत्तरदाताओं को उस पर निर्णय लेने का आदेश देने का एकमात्र अधिकार है।

(10) पहला निर्णय जिस पर भरोसा किया गया वह **पलविंदर सिंह ओबेरॉय** (सुप्रा) में है। उपरोक्त निर्णय द्वारा दो रिट याचिकाओं का निस्तारण कर दिया गया। दोनों रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने खुदरा दुकानों की स्थापना के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी "अनापत्ति प्रमाण पत्र" को चुनौती दी। याचिकाकर्ताओं की शिकायत थी कि जिन खुदरा दुकानों के लिए "अनापत्ति प्रमाणपत्र" जारी किया गया है, वे निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। एक रिट याचिका में, न्यायालय ने पाया कि कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और जिस ईंधन स्टेशन की स्थापना की मांग की गई है वह मानदंडों को पूरा करता है, जबकि दूसरे मामले में यह माना गया कि भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा जारी दिशानिर्देश निर्देशिका हैं।

(11) यहां यह ध्यान दिया जाएगा कि **पलविंदर सिंह ओबेरॉय** (सुप्रा) में निर्णय, डिवीजन बेंच **एनवायरमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया** बनाम **प्रशासक, चंडीगढ़ प्रशासन** के फैसले को संदर्भित करता है। यह न्यायालय-उपरोक्त न्यायाधीश के माध्यम से उस मामले में, चंडीगढ़ के सेक्टर 21-सी में ईंधन स्टेटिन स्थापित करने के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को आवंटन करने में चंडीगढ़ प्रशासन की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। डिवीजन बेंच. विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए, यह माना गया कि दो ईंधन स्टेशनों के बीच न्यूनतम 300 मीटर की दूरी की जरूरी है |

(12) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने **सीमा मक्कड़** बनाम **भारत संघ और अन्य** (सुप्रा) मामले में पारित आदेश पर भी भरोसा किया। उपरोक्त मामले में, याचिकाकर्ता ने स्टेशन स्थापित करने के लिए "अनापत्ति प्रमाण पत्र" देने से इनकार करने वाले पत्र दिनांक 19.08.2015 को चुनौती दी थी। लेटर्स पेटेंट अपील 1573 और 1574 ऑफ़ 2014 में 22.09.2014 को दिए गए निर्णय पर भरोसा करते हुए, न्यायालय ने माना कि अधिकारी इस मामले पर पुनर्विचार करेंगे।

(13) इस न्यायालय ने डिवीजन बेंच दिनांक 22.09.2014 के फैसले की भी सावधानीपूर्वक जांच की है। उपरोक्त फैसले में, डिवीजन बेंच ने यह देखने के बाद कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने मौजूदा प्रस्तावित खुदरा दुकानों के बीच की दूरी और सड़क चौराहे से दूरी आदि के संबंध में दिशानिर्देशों को निर्देशिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। लेटर्स पेटेंट अपील **चरण दास** बनाम **यूनियन इंडिया और अन्य (सिविल रिट याचिका संख्या 19287/2011, निर्णय 22.10.2013)** में पारित फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। उस रिट याचिका में भी, याचिकाकर्ता ने "नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट" देने से इनकार करने वाले दिनांक 06.09.2011 के आदेश को चुनौती दी थी। वास्तव में उपरोक्त फैसले में, न्यायालय ने पिछले दौर में पारित फैसले पर गौर किया, यानी 2010 की सिविल रिट याचिका 6239 में 21.07.2011 को अनुमति दी गई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि न्यायालय ने 21.07.2011 को आदेश पारित करते हुए याचिका को स्वीकार कर लिया और केवल अनुग्रह के रूप में, अधिकारियों को मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। इन परिस्थितियों में, रिट याचिका की अनुमति दी गई।

(14) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया अगला निर्णय **दुर्गादास** बनाम **भारत संघ और अन्य** (सुप्रा) में है। उस स्थिति में, याचिकाकर्ता को 03.05.2012 के आदेश के खिलाफ "कोई आपत्ति प्रमाण पत्र" जारी करने से इनकार कर दिया गया था। प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने रिट याचिका का विरोध किया।

(15) इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि किसी भी मामले में, न्यायालय ने इस मुद्दे की जांच नहीं की थी कि क्या प्रतिवादियों को छूट देने का निर्देश देने वाला परमादेश जारी किया जा सकता है। छूट से इनकार करने पर रिट याचिका दायर की जा सकती है। हालाँकि, इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में, अधिकारियों को छूट देने का निर्देश देने वाला परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। यह तय है कि ऐसे निर्देश संभवतः जारी नहीं किए जा सकते हैं ताकि किसी प्राधिकारी को ऐसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए मजबूर किया जा सके जिसमें विवेक का पर्याप्त तत्व हो।

(16) इस न्यायालय को जिस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा गया है वह यह है कि क्या डिवीजन बेंच और समन्वय बेंच द्वारा पारित निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 141- के तहत बाध्यकारी उदाहरण हैं। ऊपर उल्लिखित निर्णयों को ध्यान से पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि न तो प्रश्न उठाया गया और न ही निर्णय लिया गया। इस पहलू पर, दो सिद्धांत हैं। एक है पेर इंक्यूरियम, जबकि दूसरा है सब साइलेंटियो। इन्हें **यूपी राज्य और अन्य** बनाम **सिंथेटिक एंड केमिकल्स लिमिटेड और अन्य**[2] में सुप्रीम कोर्ट द्वारा खूबसूरती से समझाया गया है । पैरा 40 और 41 इन सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं, इसलिए, निम्नानुसार निकाले गए हैं:

> "40. 'इनक्यूरिया' का शाब्दिक अर्थ है 'लापरवाही'। व्यवहार में पेर इनक्यूरियम का अर्थ प्रति इग्नोरेटियम प्रतीत होता है।' अंग्रेजी न्यायालयों ने घूरने के निर्णय के नियम को शिथिल करने के लिए

इस सिद्धांत को विकसित किया है। 'कानून में उद्धृत करने योग्य' से बचा जाता है और इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, अगर इसे 'किसी क़ानून या अन्य बाध्यकारी प्राधिकारी की अनदेखी में' प्रस्तुत किया जाता है। (1944 आईकेबी 718 यंग बनाम ब्रिस्टल एयरप्लेन लिमिटेड_ संविधान के अनुच्छेद 141 की व्याख्या करते समय इस न्यायालय द्वारा इसे स्वीकार, अनुमोदित और अपनाया गया है जो कानून के मामले के रूप में मिसाल के सिद्धांत का प्रतीक है। जयश्री साहू बनाम राजदेवान दुबे (1962) 2 एससीआर 558 में इस न्यायालय ने इंगित करते हुए कहा जब अपीलीय न्यायालय का निर्णय बाध्यकारी नहीं होता है, तो इंग्लैंड के हेल्सबरी कानूनों से एक अंश निकालकर एक बेंच के समक्ष विरोधाभासी निर्णय रखे जाने पर पालन की जाने वाली प्रक्रिया।

41. क्या यह सिद्धांत कानून के किसी निष्कर्ष पर विस्तारित और लागू होता है, जिसे न तो उठाया गया था और न ही उस पर पहले कोई विचार किया गया था। दूसरे शब्दों में क्या ऐसे निष्कर्षों को कानून की घोषणा माना जा सकता है? यहाँ फिर से अंग्रेजी अदालतों और न्यायविदों ने मिसाल के नियम के लिए एक अपवाद बनाया है। इसे सब-साइलेंटियो के नियम के रूप में समझाया गया है। तकनीकी अर्थों में, एक निर्णय सब-साइलेंटियो पारित हुआ। उस वाक्यांश से जुड़ा होना चाहिए, जब निर्णय में शामिल कानून के विशेष बिंदु को न्यायालय द्वारा नहीं माना जाता है या उसके दिमाग में मौजूद नहीं है' (न्यायशास्त्र 12 वें संस्करण पर सैल्मंड)। लैंकेस्टर मोटर कंपनी (लंदन) लिमिटेड बनाम ब्रेमिथ लिमिटेड (1941) आईकेबी 675, 677 में न्यायालय ने पहले के फैसले से बाध्य महसूस नहीं किया क्योंकि इसे 'बिना किसी तर्क के, नियम के महत्वपूर्ण शब्दों के संदर्भ के बिना और बिना' प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकार का कोई उद्धरण'. दिल्ली नगर निगम बनाम गुरनाम कौर (1989) 1 एससीसी 101 मामले में इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था। बेंच ने कहा कि, 'उप-मौन और तर्क के बिना मिसालें कोई मायने नहीं रखतीं।' इस प्रकार न्यायालयों ने इसका सहारा लिया है। अन्यायपूर्ण उदाहरणों द्वारा किए गए अन्याय से राहत पाने का सिद्धांत। एक निर्णय जो व्यक्त नहीं है और कारणों पर आधारित नहीं है और न ही यह मुद्दे पर विचार करने पर आगे बढ़ता है, उसे बाध्यकारी प्रभाव वाला घोषित कानून नहीं माना जा सकता है जैसा कि अनुच्छेद 141 में माना गया है। एकरूपता और स्थिरता न्यायिक अनुशासन का मूल है। लेकिन जो बिना किसी अवसर के फैसले से बच जाता है, वह अनुपात निर्णायक नहीं है। एट शमा राव बनाम पांडिचेरी राज्य, एआईआर 1967 एससी 1680 में कहा गया था, 'यह कहना सामान्य है कि कोई निर्णय अपने निष्कर्षों के कारण नहीं बल्कि उसके अनुपात और उसमें निर्धारित सिद्धांतों के संबंध में बाध्यकारी है।' बिना सोचे समझे की गई या बिना किसी कारण के की गई किसी भी घोषणा या निष्कर्ष को किसी सामान्य प्रकृति के कानून या प्राधिकारी की घोषणा नहीं माना जा सकता है, जो एक मिसाल के रूप में बाध्यकारी है। असहमति या फैसले को खारिज करने में संयम स्थिरता और एकरूपता के लिए है लेकिन कठोरता से परे है उचित सीमाएं कानून के विकास के लिए हानिकारक हैं।

(17) दिशानिर्देशों में ढील देने की शक्ति केवल एक सक्षम शक्ति है जो किसी को भी अधिकार के रूप में इसकी मांग करने के लिए अधिकृत नहीं करती है। यह संबंधित कर्तव्य भी नहीं डालती है। प्राधिकार को अनिवार्य रूप से शिथिल करने का अधिकार। यह, अधिक से अधिक, सक्षम प्राधिकारी को विवेकाधिकार प्रदान करता है। इस

न्यायालय के विचार में, दिशानिर्देश निम्न के लिए हैं जनता की भलाई और सुरक्षा. यदि ईंधन स्टेशन या रेलवे पर कोई दुर्घटना होती है तो बड़ी त्रासदी से बचने के लिए इन्हें प्रदान किया गया है। इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय को परमादेश रिट जारी करना उचित नहीं लगता।

(18) हालाँकि, याचिकाकर्ता ने, वैकल्पिक रूप से, प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को प्रतिनिधित्व पर अंतिम निर्णय लेने के लिए निर्देश जारी करने की प्रार्थना की है। उपरोक्त प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता को छूट दी जा सकती है या नहीं, इस प्रश्न पर अंतिम निर्णय लेने के लिए समिति को निर्देश देकर रिट याचिका का निपटारा किया जाता है। यहां यह नोट किया जा सकता है कि इस न्यायालय ने मामले की योग्यता के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया है और समिति के सदस्य कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे।

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है| सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त रहेगा|

सुनीता